सं0– 1368/IV(2)-श0वि0–10–212(सा0)/05 टी.सी.

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक– 4 अक्टूबर ~~सितम्बर~~, 2010

विषय : नगर पालिका परिषद, भवाली जनपद नैनीताल के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत निर्माण कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 694/V–श0वि–06–212(सा0)/05 टी.सी. दिनांक 25–3–2006, शासनादेश संख्या 547/IV–श0वि0–08–212(सा0)/05 टी.सी. दिनांक 17–12–2007 तथा शासनादेश संख्या 326/IV(2)–श0वि0–09–212(सा0)/05 टी.सी. दिनांक 26–2–2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके माध्यम से **नगर पालिका परिषद, भवाली** के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु ₹ 313.26 लाख की प्रशासकीय प्रदान करते हुए क्रमशः ₹ 124.72 लाख, ₹ 80.00 लाख तथा ₹ 55.43 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 260.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासनादेश दिनांक 26–2–2009 द्वारा पार्को के सौन्दर्यकरण कार्यो हेतु न्यूनतम निविदा के सापेक्ष ₹ 25.87 लाख की बचतों का समायोजन भी किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, भवाली के पत्र संख्या 214/अव0वि0नि0/2009–10 दिनांक 3–8–2010 के माध्यम से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 25–3–2006 के माध्यम से स्वीकृत कार्यो में से क्रमांक–6 के कार्य की स्वीकृति हेतु अब अवशेष **₹–25.97 लाख (रूपये पच्चीस लाख सतानवे हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **₹–25.97 लाख (रूपये पच्चीस लाख सतानवे हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 694/V–श0वि–06–212(सा0)/05 टी.सी. दिनांक 25–3–2006 में उल्लिखित अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
5. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।

6. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
7. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
10. स्वीकृत कार्यो हेतु अवमुक्त धनराशि का दिनांक 31–3–2011 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 371/XXVII(2)/2010, दिनांक– 15 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

सं0– 1368 (1)/IV(2)-श0वि0–10,तद्दिनांक। 4-10-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, **भवाली**।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

04-01